

सीरी की कोशिश

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभयांत्रिकी अनुसंधान संस्थान तैयार कर रहा सिलिकोसिस के खिलाफ तकनीक

सिलिकोसिस से बचाने के लिए ईजाद की तकनीक, धूल को खींचकर पानी में इकट्ठा किया जा सकेगा, इससे बना सकेंगे गमले और टाइल्स

भास्कर न्यूज़ | (झुंझुनू)

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभयांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीरी) ने जानलेवा बीमारी सिलिकोसिस से बचाव की दिशा में एक बड़ी पहल की है। सीरी ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की है।

इस तकनीक को स्मार्ट स्टोन डस्ट प्रेसिपिटेटर सिस्टम नाम दिया गया है। जिसके जरिए पत्थरों की गढ़ाई करने वाले मजदूरों के आसपास से इस तकनीक के आधार पर मशीन धूल के कणों को हटा देगी और यह उनके फेफड़ों में नहीं जाएगी। सिलिकोसिस एक वेहद जानलेवा बीमारी है। पत्थर

गढ़ाई करने वाले शिल्पकारों, माईंस में काम करने वाले मजदूरों में ज्यादा फैलती है। राजस्थान में इसके करीब 21 हजार मरीज हैं। जिनमें सर्वाधिक सिरोही व करौली जिले में हैं। सीरी ने इस मशीन का सिरोही के समीप पिंडवाड़ा में ही प्रयोग भी किया है जो सफल रहा है।

अब आगे क्या : सीरी ने इसे विकसित कर इसका प्रयोग भी किया है। जो सफल रहे। अब इसकी तकनीक किसी कंपनी को ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए कंपनी व सीरी के बीच एमओयू होगा। वह कंपनी इसे डेवलप कर बाजार के लिए तैयार करेगी और इसकी कीमत तय होगी।

बिजली से चलेगी, एक या चार लोगों के बीच करेगी काम

सीरी की ओर से विकसित की गई यह मशीन पोर्टेबल है और वैक्यूम तकनीक की तरह काम करती है। इसमें लगा पाइप धूल के कणों को हवा से अलग कर अपनी ओर खींच लेगा। वातावरण में धूल खत्म हो जाएगी। यह धूल स्टोर टैंक में भरे पानी में इकट्ठा होगी। ताकि वापस ना उड़ सके। धूल के इस मिश्रण को ड्रेन वाल्व से बाहर निकाला जा सकेगा। इसके बाद इसमें सोफ्ट सीमेंट मिलाकर इससे अन्य उत्पाद जैसे कि गमले, मूर्तियां, टाइल्स आदि बनाई जा सकती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे एक मजदूर और चार मजदूरों के बीच वेहद आसानी से काम में लिया जा सकता है। यह बिजली से चलती है और ऑटोमैटिक है।



राजस्थान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि यहां इसके 21 हजार मरीज

सिलिकोसिस वेहद जानलेवा बीमारी है। राजस्थान में इसके करीब 21 हजार मरीज हैं। प्रदेश सरकार इसके लिए नई नीति बनाने जा रही है। सिलिकोसिस नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। नीति में सिलिकोसिस ग्रस्त रोगियों को 5 लाख की सहायता राशि के अलावा 4 हजार रुपए प्रतिमाह की पेंशन सहित अन्य लाभों का प्रावधान है। प्रदेश में

सबसे पहले करौली जिले से वर्ष 2011 में सिलिकोसिस की पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आई थी। इसके बाद राज्य व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसके बचाव व मरीजों की सहायता के लिए कई कदम उठाने की पैरवी की। वर्ष 2016 में वर्किंग टास्क फोर्स का गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले सरकारों को दिशा निर्देश जारी कर चुका है।

प्रदेश में कई जिले प्रभावित

इस बीमारी के कारण प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं खासकर सिरोही जिले पिंडवाड़ा के आसपास कई ऐसे गांव हैं जहां श्रमिक मौत का शिकार बने। वहां के रानीधरा गांव में तो स्थिति यह है कि कोई एक दो पुरुष ही देखने को मिलते हैं। अधिकांश घरों में लोग इसका शिकार हैं। इस बीमारी में धूल के कण सांस के साथ फेफड़ों में जमा हो जाते हैं और यह धूल फेफड़ों के ऊपरी भागों में घाव बना देते हैं।

उपयोगी साबित होगी : सीरी ने अपने सामाजिक सरोकारों के तहत यह मशीन डिजाइन और डेवलप की है। सिलिकोसिस से अत्यधिक प्रभावित सिरोही जिले में हमने इसकी ट्रायल की। जहां अच्छे परिणाम आए।

- डॉ. डीके असवाल, डायरेक्टर सीएसआईआर-सीरी

काफी सफल रही मशीन : सीरी ने यहां यहां आकर पहले इस समस्या को देखा और जब दूसरी आर आर तो वे यह मशीन बनाकर लाए। हमने पिंडवाड़ा में इसका ट्रायल लिया। इसके परिणाम काफी अच्छे थे और हमें लगता है कि इससे समस्या का काफी हद तक समाधान होगा।

- डॉ. संजय गहलोत, जिता क्षम रोग अधिकारी, सिरोही